चीन ने कैंसर का सफाया करने का फैसला लिया

चीन सरकार ने 'कैंसर गांवों' के अस्तित्व को स्वीकार कर कहा है कि जिन क्षेत्रों में कैंसर का प्रकोप ज़्यादा है उन क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई के पानी में उद्योगों और कृषि का दूषित पानी जाने की संभावना भी ज़्यादा है।

कैंसर क्लस्टर्स का ज़िक्र चीन की रसायनों के पर्यावरण प्रबंधन सम्बंधी पहली पंचवर्षीय योजना में किया गया है जो 20 फरवरी को प्रस्तुत हुई है। इसमें जल प्रदूषण का सम्बंध स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं से जोड़ा गया है और कहा गया है कि जल प्रदूषण के कारण ही कई गांव 'कैंसर गांव' बन गए हैं।

हाल के आंकड़ों के अनुसार चीन में सन 1970 से 2004 के बीच कैंसर से मरने वालों की संख्या में 80 प्रतिशत का इज़ाफा हुआ है। शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 21 प्रतिशत मौतें इसी बीमारी की वजह से होती हैं। अलबत्ता चीन के लोगों को 75 वर्ष की उम्र से पहले कैंसर का खतरा 18.9 प्रतिशत है जबकि यूएस में 29.9 प्रतिशत और यूके में 26.3 प्रतिशत है।

'कैंसर गांव' शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 2008 में शानडोंग स्थित डेज़ाऊ विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किया था। उनके अध्ययन में पता चला था कि मात्र 1200 आबादी के इस गांव में पांच साल की अवधि में 80-100 लोगों की मृत्यु कैंसर से हुई थी।

सिडनी विश्वविद्यालय के एपिडिमियोलॉजिस्ट टिम ड्रिस्कोल का कहना है कि कैंसर और प्रदूषण के बीच कड़ी को साबित करने के लिए और अधिक विस्तृत प्रमाणों की ज़रूरत है। वैसे उनका मत है कि कैंसर से सम्बंध हो या न हो, घातक प्रदूषण को साफ किया जाना चाहिए।

योजना भी यही है। चीन के पर्यावरण सुरक्षा मंत्रालय ने 58 रसायनों की एक सूची तैयार की है। इसमें संदिग्ध कैंसरजनों और अंतःस्रावी तंत्र में गड़बड़ियां पैदा करने वाले रसायनों को रखा गया है। 2015 तक इस सूची को दो भागों में बांटा जाएगा - कुछ रसायनों का पूरी तरह से सफाया किया जाएगा, कुछ की मात्रा को कम किया जाएगा।

बीजिंग में ग्रीनपीस ईस्ट एशिया के कार्यकर्ता यिक्सियू वू के अनुसार कुछ रसायनों को पूरी तरह से हटा देने की योजना तो बहुत बड़ा कदम होगा, इन रसायनों को तो काबू में करने का कदम भी बहुत सराहनीय होगा।

बीजिंग के इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड एन्वायर्मेंट अफेयर्स की सबरीना ओर्लीस का कहना है कि यह महत्वपूर्ण बात है कि सरकार इस परेशानी को समझ रही है और यह अधिक पारदर्शिता दर्शाता है। उनका यह भी कहना है कि जब पर्यावरण सम्बंधित जानकारी बढ़ेगी तब लोगों में इसके प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। लोग उद्योगों पर दबाव बनाएंगे।

वू के अनुसार इस योजना में जवाबदेही सुनिश्चित करने की कमी है। सरकार को फैक्ट्री के स्थानों और पर्यावरणीय जोखिम की जानकारी सार्वजनिक करना चाहिए। यह जानकारी उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो फैक्ट्री के नज़दीक रहते हैं। दरअसल इस योजना का मकसद यही है कि लोगों में जागरूकता बढ़े और सरकार प्रदूषण सम्बंधी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुमोदन करे। ***(स्रोत फीचर्स)***